Hindustan Times

NEW DELHI WEDNESDAY MARCH 01, 2023

DDA okays 2041 Master Plan, paves way for better nightlife

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Develop ment Authority (DDA) on Tues-day approved the Master Plan of Delhi-2041, which aims re-imag-ine the Capital as a 24x7 city with night-circuits, provide lib eral development norms for

group housing societies, schools and industry and push land pooling to cater to the growing housing demand in the city, officials aware of the matter said.

The vision document will now be sent to the Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) for a final notificaMaster Plan, which came into force on February 7, 2007

Senior DDA officials who attended the meeting, which was chaired by lieutenant governor VK Saxena, said there are no major changes in the final plan compared to the original

Development road map for next 20 yrs approved

HT Correspondent

htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Tuesday approved the draft Master Plan of Delhi-2041 that seeks to re-imag-ine the national capital as a 24X7 city with night circuits; provide liberal development norms for group housing societies, schools and industry; and push land pooling to cater to the growing housing demand in the city, officials aware of the matter said.

The vision document will now be sent to the Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) for final notification. The new plan will replace the Master Plan of Delhi-2021, which came into force on February 7, 2007. The draft MPD-2041 was tabled before the authority on Tuesday after incorporating changes based on the 33,000 suggestions and objections received from the public, the officials said. DDA placed the draft plan in the public domain in June 2021.

Senior DDA officials who attended the meeting, which was chaired by lieutenant governor (LG) VK Saxena, said there are no major changes in the final plan compared to the original one.

In a statement on Tuesday, Saxena said, "The thrust of MPD-2041, was inclusive development, environmental sustainability, green economy and infrastructure development that included sufficient housing for all sections of the society, innovative interventions such as Transit-oriented Development hubs, land pooling, green area development and rejuvenation and regeneration (developed areas) of the city."

DDA officials said that the new Master Plan provides for policies such as Green area development which is aimed at planned development on the city periphery, and regulated growth of farmhouses.

It also aims to promote nighttime economy to make the national capital a 24x7 city. It envisages 24X7 restaurants, night circuits around cultural precincts, and heritage areas.

The plan incorporates the amendments proposed by the Centre last year for swift imple-

Vision for a 24X7 city

SHELTER AND SOCIAL INFRA

- Increased ground coverage and Floor Area Ratio for schools, guesthouses, hostels, foreign missions
- Flexibility in distribution of land use in land pooling areas Arnalgamation of plots irrespective of plot size
- Developers to get FAR of 400 for remunerative component for in-situ slum rehabilitation projects

COMMERCIAL AND INDUSTRY

 FAR for commercial activity in hotels increased to 40% Multi-utility zone for street vendors in commercial areas

NATURE AND HERITAGE

- Transferable Development Rights to conserve heritage property
- Promotion of night time economy and night-time circuits
- Emphasis on development of city hubs, circuits, plazas, and night-time circuits
- Rejuvenation of Yamuna riverfront

INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

 Mandatory EV charging stations in parking lots Preparation of Comprehensive Mobility Plan (CMP) to

- integrate land use and transportation Dynamic parking charges and preparation of parking management plans
- Restricting on-street parking

TOTAL DE

Preparing walk plans to enhance walkability



READ: Check HT's special package on how MPD-2041 envisions Delhi as a 24X7 city

mentation of the land pooling policy, which has been hanging fire for nearly a decade now. According to the plan, land owners will now be allowed to merge their property irrespective of their plot sizes. Earlier, the policy required 70% contiguous land parcels to create a sector.

The new plan provides several concessions in terms of Floor Area Ratio (FAR) to schools, guest houses, hotels and foreign missions allowing them more developed space. Floor Area Ratio (FAR) is the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.

Also to incentivise the develop ers involved in the construction of in-situ slum rehabilitation projects, the MPD 2041 provides for a higher FAR for commercial component to help them recover cost, DDA officials said.

The meeting also witnessed its share of politics with the Bharatiya Janata Party (BJP) leaders, who are members of DDA, accusing the Aam Aadmi Party (AAP) for politicising MPD-2041. They were referring to a letter by AAP MLA Somnath Bharti who had urged the LG to postpone the meeting

"I am more worried about this hasty act in view of the developments in excise policy. Though the MPD-2041 will be passed in the meeting chaired by you but just like excise policy, it is not you who will be held responsible and be targeted. Just like Manish Sisodia, the AAP will be held responsible for its failure, "Bharti said.

Though the LG office did not comment on the letter, the BJP hit back at Bharti and said that the

AAP was politicising the matter.

BJP MLA Vijender Gupta. who is a member of DDA, said, They (AAP) are politicising the issue and just trying to delay the

हिन्दुस्तान

नर्ड दिल्ली, बघवार, १ मार्च २०२३

DATED-

दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी मिली

दिल्ली के मास्टर प्लान-2041 पर मुहर लग गई है। इसमें 'जहां झुगी, वहां मकान' योजना के तहत अकेली महिला को भी प्लैट मिलेगा। **P05**

'जहां झुग्गी वहां मकान' योजना में कई बदलाव किए, केंद्र सरकार के पास मसौदा भेजा

मास्टरप्लान-2041 पर मुहर, अकेली महिला को फ्लैट मिलेगा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम तक चली बैठक में मास्टर प्लान-2041 पर अंतिम मुहर लगा दी गई। इसके नए स्वरूप में कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब 'जहां झुगी वहां मकान योजना' के तहत अकेली महिला को भी फ्लैट का आवंटन किया जा सकेगा।

वहीं, नए मास्टर प्लान में नाइट लाइफ को बढ़ावा और प्रदूषण को कम करने पर भी ध्यान दिया गया है। मास्टर प्लान को अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि कालकाजी में फ्लैट आवंटन के दौरान एक समस्या खड़ी हुई थी। कई आवंटी ऐसी महिलाएं 33

हजार से अधिक आपत्तियां और सुझाव मिले थे

02

करोड़ 92 लाख आबादी के हिसाब से प्लान तैयार किया

थीं, जिनके पित की मृत्यु हो गई थी या तलाक हो गया था या किसी अन्य कारण से पित, महिला के साथ नहीं था। डीडीए ने अब इन फ्लैट के आवंटन में अकेली महिलाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2041 तक दिल्ली की आबादी 2.92 करोड़ हो जाएगी।



उपराज्यपाल वीके सक्सेना।

इसके अनुसार ही प्लान तैयार किया गया है। प्लान के अनुसार, किराये के किफायती आवास, पूरी सुविधाओं वाले रिहायशी क्षेत्र और छोटे प्रारूप वाले मकान राष्ट्रीय राजधानी में आवास विकास के कुछ प्रमुख बिंदु होंगे। मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट को तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में मंजरी दी गई थी। इसके डाफ्ट पर 33

जल्दबाजी में पास न करें : सोमनाथ

बैठक शुरू होने से पहले आप विधायक और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिख कर जल्दबाजी न करते हुए मास्टरप्लान 2041 की बैठक को स्थगित करने की मांग की। उन्होंने पिछले मास्टर प्लान 2021 की याद दिलाई, जिसमें जमीनी हकीकत पर ध्यान न देने के कारण 500 से अधिक संशोधन करने पड़े थे।

हजार से अधिक आपत्तियां और सुझाव मिले। सभी आपत्तियों एवं सुझावों को जनसुनवाई के माध्यम से सना गया।

महरौली वासियों से कोर्ट ने दस्तावेज मांगे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महरौली में गोशिया कॉलोनी झुग्गी वासियों के बकील से 467 लोगों के पहचान दस्तावेज देने करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता डीडीए की ओर से कॉलोनी के तोड़ने के आदेश को मुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने अधिवक्ता अनुप्रधा सिंह से बुधवार तक डीडीए और डीयूएसआईबी के वकील को पहचान दस्तावेजों की एक सूची देने को कहा है। पीठ ने उन्हें डीडीए और डीयूएसआईबी की ओर से दायर

- 4.67 लोगों से दस्तावेज देने को कहा गया
- मामले में अगली सुनवाई
 14 मार्च को होगी

हलफनामों पर एक प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी कहा है। अधिवक्ता अनुप्रधा ने हलफनामों पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है।

डीडीए ने अपने हलफनामें में कहा है कि विचाराधीन भूमि महरौली पुरातत्व पार्क में आती है जो दक्षिणी मध्य रिज का हिस्सा है, जहां बड़ी संख्या में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध स्मारक मौजूद हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित/असंरक्षित और अनुरक्षित है। इस भूमि को शुरू से ही दिल्ली के मास्टर प्लान में हरे रंग के रूप में चिह्नित किया गया है और इसे हरित के रूप में विकसित और बनाए रखा जाना है। यह इलाका महरौली विरासत क्षेत्र के तहत संरक्षित किया जाना है।

याचिका में कहा गया है कि गोशिया स्लम कॉलोनी 50 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। यहां पर लगभग 4,000 आबादी वाले 700 से अधिक घर हैं। बताया जाता है कि यह कालोनी खसरा संख्या 217, 216 269, 368/220, 869 एवं 870 में स्थित है। 216 और 217 महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है, हालांकि, डीडीए पूरी गोशिया कॉलोनी को गिराने का दावा कर रहा है।

NAME OF NEWSPAPERS-

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 1 मार्च 2023

दिल्ली में ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजुरी



 विस, नई दिल्ली : डीडीए ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी। यह 20 साल में दिल्ली के विकास की गति तय करेगा। LG वीके सक्सेना ने कहा, इसे विकास, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड पुलिंग आदि मकसद से तैयार किया है। स्वस्थ वातावरण, अच्छा शहर बनाना, इकॉनमी बढ़ाना लक्ष्य होंगे। अब शहरी विकास LG वीके सक्सेना मंत्रालय इसे ऑतिम मंजूरी देगा। ▶ पेज 9

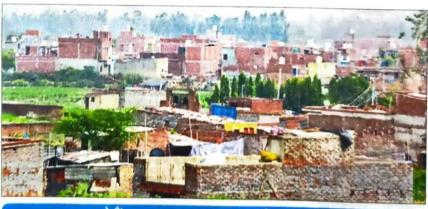
मास्टरप्लान-2041 से अगले 20 साल डिवेलपमेंट के नाम

दिल्ली के विकास को मिलेगी रफ्तार, तय होगी रूपरेखा विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए ने मंगलवार को डाफ्ट मास्टरप्लान-2041 को मंजूरी दे दी है। मास्टरप्लान अगले 20 साल तक राजधानी के विकास की गति और रूपरेखा तय करता है। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि इसे विकास, पर्यावरण, ग्रीन इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लैंड पुलिंग, ग्रीन एरिया, शहर को बेहतर बनाने के मकसद के साथ तैयार किया गया है।

मीटिंग में डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाषित पांडा के साथ अन्य सदस्य भी शामिल हुए। डीडीए से मंजूरी के बाद = मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अबंन अफेयर इसे ऑतम अप्रवल देगी और नोटिफाई करेगी। हापर मास्टरप्नान-2041 को दो भागों और 10 चैप्टर में बांटा गया है। इस " फ्लान के तीन लक्ष्य है।

वहीं दूसरी और आप विधायक और डीडीए के सदस्य योमनाथ भारती ने उपराज्यपाल ू और डीडीए अध्यक्ष विनय कृमार सक्सेना को पत्र लिखा है। इसमें 2041 के दिल्ली मास्टरप्लान को जल्दबाजी में पारित करने के एजेंडे का विरोध किया है। उन्होंने एलजी को पिछले मास्टरप्नान 2021 की याद दिलाई, जिसमें जमीनी हकीकत पर ध्यान न देने के कारण 500 से अधिक संशोधन करने पढ़े थे।



ये हैं ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 की खास बातें

- ब्लु-ग्रीन संपत्ति पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें बायोडायवर्सिटी पार्क, फ्लडप्लेन प्लानिंग, बावली और झीलों और तलाबों को पूनर्जीवित करना. नालों के किनारे को सुंदर बनाकर वहां साइकलिंग और पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाना शामिल है।
- क्लीन इकोनॉमी के लिए इसमें खास प्लान है। इसमें आईटी हब, साइबर हब, नॉलेज बेस्ड इंडस्टी, आर एंड डी फैसिलिटी के लिए प्रस्ताव है। नई इंडस्टी हाइटेक और सर्विस बेस्ड होगी।
- स्ट्रैटजी हब और सेंटर के डिवेलपमेंट का प्रस्ताव भी है। इसमें बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्स, टीओडी (ट्राजिट ओरिएटेड डिवेलपमेंट) के साथ मौजदा डिस्टिवर सेंटर्स को आधुनिक बनाना शामिल है।
- यमुना और बाढ़ क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए यमुना नदी के लिए रिवर डिवेलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। होरिटेज जोन, ऑकॉलॉजिकल पार्क,
- कल्चरल हब और अन्य संरक्षित हेरिटेज बिल्डिगों के लिए नियम तय किए।
- कल्क्सल और एंटरटेनमेंट हब डिवेलप करना इसमें शामिल है।
- सिटी हब, सर्किट, प्लाजा, नाइट टाइम सर्किट को डिवेलप करने के साथ नाइट टाइम इकोनॉमी को बदावा देने के लिए कॉरिडोर आदि की पहचान करना।
- प्राइवेट हिस्सेदारी बढ़ाकर हाउसिंग की जरूरतों को पूरा करना। इसमें लैंड पुलिंग के साथ प्लान और अनप्लाड एरिया के लिए रिजनरेशन प्लान शामिल है। एफएआर का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 🔳 नॉन ओनरशिप, रेंटल हाउसिंग और अफोर्डबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को डिवेलप करना। यह मास ट्रांजिट एरिया के आसपास होंगे। इनमें सर्विस अपार्टमेंट, होस्टल, स्टूडेंट हाउसिंग, वर्कर हाउसिंग जैसी सुविधा होंगी।
- पार्किंग मैनेजमेंट के लिए प्लान के साथ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है। इसमें ई-वीकल और ई-चार्जिंग इन्फ्रास्ट्क्चर को बढ़ावा दिया गया है।
- ट्रीटेड वॉटर के इस्तेमाल को बढ़ाने. ड्यूल पाइपिंग सिस्टम, ग्रीन रेटिंग, रिन्युबल एनर्जी, रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्टैटेजी बनाना।
- जीआईएस पर आधारित लैंड युज प्लान विकसित किया जाएगा।

NAME OF NEWSPAPERS

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 1 मार्च 2023

गहलोत और आनंद संभालेंगे विभाग, जल्द मिलेंगे 2 नए मंत्री

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब कैबिनेट में शामिल होने वाले नए चेहरों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के सूत्रों से पता चला है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास जिन 18 विभागों का जिम्मा था, उन्हें फिलहाल मंत्री कैलाश गहलीत और राजकुमार आनंद संभालेंग। दोनों के बीच इन विभागों का बराबर-बराबर बंटवारा किया जाएगा।

गहलोत के पास अभी ट्रांसपोर्ट और रेवेन्य समेत 6 विभागों का प्रभार है। अब उन्हें पीडब्ल्यूडी, पावर, वॉटर, फाइनैंस और होम समेत 8 विभाग और सौंपे जा सकते हैं। इसी तरह मंत्री राजकुमार आनंद के पास अभी समाज कल्याण और सहकारिता समेत 4 विभाग हैं। अब एजुकेशन, हेल्थ, लेबर, विजिलेंस, ट्रिज्म जैसे 10 अन्य महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा उन्हें सौंपे जाने की संभावना है। सत्येंद्र जैन के पास कोई विभाग नहीं था। सुत्रों ने बताया है कि मंत्रियों को नए सिरे से विभाग एलोकेट किए जाने का आदेश देर शाम सीएम ऑफिस से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को भी सीएम ने एलजी की मंजूरी के लिए भेज दिया है। दोनों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद नए मंत्रियों की नियुक्ति के लिए अलग से फाइल भेजी जाएगी। हालांकि, इसमें कुछ वक्त लगने के आसार हैं।

इस बीच आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री परिषद में केवल 6 मंत्री होते हैं। दिल्ली के लोगों के काम न रुके, इसलिए मनीष सिसोदिया और सत्यंद्र जैन की जगह जल्द ही दो नए मंत्री बनाए जाएंगे। उनका कहना था कि इसकी कोई टाइमलाइन तय नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसी जानकारी है कि



कैलाश गहलोत

अभी ट्रांसपोर्ट
 और रेवेन्यू समेत
 6 विभागों का
 प्रभार है।
 अब पावर,
 पीडब्ल्यूड़ी, वॉटर,
 फाइनैंस और होम
 समेत 8 विभाग
 और सौंप जा
 सकते हैं।



राजकुमार अभी समाज कल्याण और सहकारिता समेत

4 विभाग है।
■ अब एजुकेशन, हेल्थ, लेबर, विजलेंस, टूरिज्म जैसे 10 अन्य विभाग और सौंपे जा सकते हैं।

दो नए चेहरे मंत्रीमंडल में शामिल होंगे। उनके इस बयान के बाद ही मंत्री पद की रेस में शामिल नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

रेस में आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, दर्गेश पाठक, संजीव झा, सोमनाथ भारती. राखी बिडलान के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती तो पहले भी दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सौरभ अब दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, तो वहीं सोमनाथ भारती डीडीए के मेंबर हैं। आतिशी लंबे समय से मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा में सधार के लिए काम करती आ रही हैं। दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, राखी बिइलान जैसे युवा विधायकों को भी सरकारी कामकाज का अनुभव है। ऐसे में केजरीवाल इनमें से किसी को मौका दे सकते हैं। इन्हें सीएम या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का विश्वासपात्र भी माना जाता है। माना जा रहा है कि नए चेहरों को मौका देकर सीएम दिल्ली सरकार में एक नई युवा लीडरशिप को डिवेलप करने का रास्ता भी खोल सकते हैं।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI * WEDNESDAY, MARCH 1, 2023

DUSIB has no role in demolitions in Mehrauli, HC told

New Delhi: The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) on Tuesday told the Delhi High Court that it has no role in the demolition drive proposed by the Delhi Development Authority (DDA) in Mehrauli or rehabilitation of displaced residents.

DUSIB said the land-owning agency is the DDA and the board has no role to play in the petition filed by Ghosiya Slum Colony in Mehrauli, which was to be demolished by the authorities. The matter came up before Justice Manmeet Pritam Singh Arora, who listed it for further hearing on March 14.

DUSIB said no joint survey of the colony has been carried out with the representatives of DDA as per the Delhi Slum Rehabilitation Policy of 2015 and "since the land owning agency in this case is DDA, therefore, any steps as for the rehabilitation, relocation or under in-situ up-gradation, if at all to be done, needs to be done by the DDA".

DDA, which also filed an affidavit, said factually the colony is not a slum cluster and it is evident from the image taken from Google Earth of Ghosiya Colony of 2006, 2008 and 2010 that the "entire area was green".

The court has passed an interim order directing the authorities to maintain the status quo on 400 jhuggis of the slum colony. PTI

NAME OF NEWSPAPERS। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 1 मार्च 2023 ATED

कॉलोनी : दिल्ली : मेरा शहर

रू फिर भी भर रहा पाना

पिछले कई हफ्तों से लोग झेल रहे हैं गंदगी और बदबू

शालीमार बाग : बिना मज़बूत बेस के लगाए झुले

एनबीटी न्यूज, शालीमार बाग : शालीमार बाग स्थित रामस्वरूप ठाकुर दास पार्क में करीब महीने भर पहले बच्चों के लिए झले लगाए गए थे, लेकिन अभी तक इनके बेस को मजबूत नहीं किया गया है। इसके साथ ही यहां पर कुछ झले वैसे ही खले रखे हैं। इसकी वजह से यहां बच्चे गिरकर चोटिल होते हैं। लोगों ने डीडीए के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। विभाग से मांग है कि वह तुरंत बचे हुए काम को पूरा करे और लगाए गए झुलों के बेस को मजबूत बनाए।

स्थानीय आरडब्ल्यूए एवं जागरुक उपभोक्ता मंच के जनरल सेक्रेटरी सतपाल शर्मा ने बताया कि इस पार्क में ओपन जिम की फ्लोरिंग पिछले एक माल से बदहाल है। इसके कारण जब कोई वहां पर एक्सरसाइज के लिए जाता है, तो गिरकर चोटिल हो जाता है। इस पार्क में जिस जगह पर बच्चों के लिए झले लगाए जा रहे हैं। वहां पर रेत डाली गर्डे है। तेज हवा चलने पर ये उड़कर बच्चों की आंखों में चली जाती है। विभाग को चाहिए कि यहां पर घास या फिर दसरी फ्लोरिंग की व्यवस्था करे। पार्क में घुमने आए दूसरे लोगों ने बताया कि कई झुलों के एंगल लगे हैं, लेकिन झुला नहीं लगाया गया है।



बना रहता है हादसे का डर



इस तरह से निकलते हैं राहगीर

🏿 एनबीटी न्यूज, नांगल राया

नांगल राया इलाके में करीब दो हफ्तों से सीवर का पानी गलियों में बह रहा है। लोगों का कहना है कि घरों के भीतर तक भी गंदा पानी जा रहा है। सीवर के

लोगों ने कहा,

हर तीन महीने

में हो जाती है

ओक्रफ्लो की

समस्या

गंदे पानी से आती बदबु की वजह से भी परेशानी होती है। वहीं प्रशासन की तरफ से काम शुरू तो कर दिया

गया है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। लोगों ने बताया कि यहां हर तीन महीने में सीवर ओवरफ्लो की समस्या हो जाती है।

स्थानीय निवासी हरनाम सिंह उर्फ मोनू ने बताया कि अनिल आटा चक्की के पास वाली गली में सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। सीवर का गंदा पानी पूरी बार उनके कपड़े खराब हो जाते हैं।

गली में भरा हुआ है। मोनू ने बताया कि यह समस्या पिछले 15 दिनों से है। यहां नियमित सफाई नहीं होने के कारण सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं। जिससे आने-जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है।

मोन ने बताया कि सोशल मीडिया पर समस्या को लेकर विडियो डालने के बाद संबंधित प्रशासन के अधिकारी यहां आए तो लेकिन कोई काम नहीं हुआ। गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं। जिससे बीमारी फैलने का डर भी बना हुआ है।

इलाके में रहने वाले राजेश और सागर कुमार ने बताया कि लोगों को मजबूरन गंदे से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वालों को हो रही है। गंदे पानी के छीटे पड़ने के कारण कई

बाहर तक फैल जाती है

■ एनबीटी न्यूज, नांगल राया : दिल्ली और एक पोस्ट ऑफिस हैं। कूड़े के ढेर के काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बस और वैन इसी रास्ते से आती हैं।

कूड़ाघर होने के बावजूद कुछ लोग सड़क पर ही कुड़ा फेंकते हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

यहां रहने वाले राजकुमार कनौजिया ने बताया कि मेन रोड

है। कुड़ाघर से कुछ दरी पर दो डिस्पेंसरी

के नांगल रायाँ इलाके में रोड पर फैली कारण सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों गंदगी से आस-पास के लोग और राहगीर को होती है। सबह और दोपहर को स्कुल

कुड़े के ढेर पर

आवारा जानवरों

का लगा रहता है

जमावड़ा, इससे

हादसों का रहता

यहां रहने वाले राज पाल तंवर ने बताया कि आवारा जानवर भी कूड़े में खाने की तलाश में पहुंचते हैं। इस वजह से कूड़ा रोड पर फैल जाता है। इन जानवरों की वजह से सड़क हादसों का भी डर बना रहता है।

पर कई महीनों तक कूड़े का ढेर लगा रहता बिट्ट ने बताया कि निगम की अनदेखी के कारण कुड़े का ढेर लगा हुआ है।



दैनिक जागरण

NAME OF NEWSPAPERS--- नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

भविष्य की बेहतर दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट को दी गई मंजूरी

समावेशी विकास, ग्रीन इकोनमी व पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी विकास और तरक्की के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष व उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। एलजी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान 'जहां झुग्गी, वहां मकान' के तहत इन सीटू पुनर्वास योजना के लिए महिला लाभार्थियों को संबंधित दिशा-निर्देशों में ढील देने का भी फैसला लिया गया।

साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में एलजी ने कहा कि मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट में समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रीन इकोनमी, आधारिक संरचना के विकास पर जोर दिया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गी के लिए पर्याप्त आवास, टीओडी हब, लैंड पुलिंग, हरित क्षेत्र का विकास, शहर का कायाकल्प और पनरोद्धार जैसी नई परिकल्पनाएं शामिल हैं। इसके अलावा मास्टर प्लान में आईटी/साइबर हब, ज्ञान आधारित उद्योगों और दिल्ली में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं जैसी स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं को बढावा देने के साथ नाइट इकोनमी के विकास के लिए भी प्रविधान है।

डीडीए मास्टर प्लान में लैंड पूलिंग और रिजेनरेशन के माध्यम से निजी भागीदारी से आवास की

क्या है मास्टर प्लान

मास्टर प्लान-2041 डीडीए द्वारा तैयार एक सांविधिक दस्तावेज है, जो वर्तमान स्थिति का आकलन करता है और वांछित विकास को प्राप्त करने हेत मार्गदर्शन करके दिल्ली के विकास को सगम बनाता है। ड्राफ्ट एमपीडी-2041 शहर के भावी विकास को दिशा प्रदान करने के लिए एक 'कार्यनीतिक' और 'सक्षम' ढांचा है, जो पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आघार पर बनाया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनभवों पर आधारित है। दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में लागू किया गया था। इन योजनाओं को 20 वर्ष के लिए तैयार किया गया है और ये दिल्ली के नियोजित विकास के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करते हैं।

काम्प्लेक्स को बढावा देने का

प्रविधान इस इस मास्टर प्लान का

प्रमुख हिस्सा है। औद्योगिक प्लाट



वीके सक्सेना • जागरण आर्काडव

- अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स को मिलेगा बढावा
- ग्रप हाउसिंग को 40 प्रतिशत तक गाउंड कवरेज
- वैकल्पिक साइटों पर निम्न आय वर्ग के लिए मकान बनेंगे
- औद्योगिक प्लाट पर वर्कर हाउसिंग पर दिया गया जोर
- पार्किंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना भी होगा अनिवार्य

बैठक स्थगित करें : भारती राब्यू, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने मंगलवार को एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर मास्टर प्लान-2041 पर निर्णय लेने संबंधी बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया। बैठक की तैयारी के लिए दस्तावेज को पढ़ने के लिए समय की कमी का हवाला देते हुए अनिधकृत कालोनियों के विकास का मुद्दा भी उठाया। भारती ने एलजी को याद दिलाया कि आबकारी नीति सहित अन्य नीतिगत फैसलों पर अंतिम निर्णय एलजी लेते हैं, जबकि उसकी अंतिम जिम्मेदारी दिल्ली के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कंधों पर आ जाती है। दिल्ली के पिछले 'मास्टर प्लान-2021' में कम-से-कम 500 संशोधन किए गए थे, क्योंकि यह विचार किए बिना पारित किया गया था। निवासियों के पहचान दस्तावेज पेश करें याचिकाकर्ता : हाई कोर्ट

महरौली ध्वस्तीकरण प्रकरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्लीः महरौली में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठन को निर्देश दिया कि 467 स्थानीय निवासियों के पहचान दस्तावेज पेश करें। पीठ ने याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अनुप्रदा सिंह को निवासियों के पहचान दस्तावेज की सूची दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (ड्रिसिब) के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही डीडीए व डूसिब द्वारा दायर हलफनामे पर प्रत्युत्तर भी दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर डूसिब अधिकारियों ने कहा उनकी इसमें भूमिका नहीं है।

आपर्ति को बढावा देना चाहता है। मास्टर प्लान में कंप्रिहेंसिव रिवर जोर दिया जाएगा। डेवलपमेंट प्लान के तहत यमुना व उसके बाढ़ क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा हेरिटेज जोन व आर्कियोलाजिकल पार्क सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमा तय की गई है। इसमें 25 से 60 वर्गमीटर के स्माल फार्मेंट हाउसिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी व निजी क्षेत्रों की मदद से अफॉडेबल रेंटल हाउसिंग

पर वर्कर हाउसिंग पर भी काफी

वहीं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए 40 प्रतिशत तक का ग्राउंड कवरेज व वैकल्पिक साइटों पर ईडब्लयएस हाउसिंग का प्रविधान भी मास्टर प्लान में किया गया है। इसके अलावा फारेन मिशन को बढ़ा हुआ ग्राउंड कवरेज व एफएआर देने की बात भी मास्टर प्लान में शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कुलों के अपग्रेडेशन के लिए भी बढ़ा हुआ एफएआर दिया जाएगा। वहीं, रेजीडेंशियल एरिया में हास्टल बनाए जाएंगे।

अब पार्किंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना भी मास्टर प्लान में अनिवार्य किया गया है।

बता दें कि एमपीडी-2041 का डाफ्ट नागरिक और स्टेक होल्डरों की व्यापक भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, आरडब्ल्यए, ट्रेडर्स और मार्केट एसोसिएशन, एनजीओ, संगठन, प्रोफेशनल्, विशेषज्ञ और आम व्यक्तियों के विचार शामिल किए गए हैं। प्राधिकरण की बैठक में डीडीए वीसी सुभाषीश पंडा और अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, MARCH 1, 2023

DDA Eyes Inclusive Growth, Looks To Give Night Economy & Infra A Boost

Conservation Of Heritage Sites Also In Focus As LG Gives His Nod To Master Plan 2041 Draft

New Delhi: Lieutenant gover nor VK Saxena approved the Delhi Master Plan 2041 on Tuesday in a meeting with Delhi Development Authority. The new plan provides for inclusive development of the city land, environmental sustainability, green economy, sufficient housing for all, and innovative interventions such transit-oriented development hubs, land pooling and rejuvenation and regeneration of certain areas. DDA updated MPD41 on the direction of the LG in a me eting held some time ago.

The plan also addresses Delhi's night-time economy, heritage conservation, mix-vertical development and slum rehabilitation in the city. Though the draft MPD41 talked about the night economy in general terms, DDA, on the LG's recommendation, has now identified specific circuits to be developed. Similarly, DDA has also identified cultural precincts and heritage zones to be developed to boost tourism.

A DDA official said, "Connaught Place, Chandni Chowk-Darvagani, Khan Market and Hauz Khas will be developed as food and shopping circuits, while Coronation Pillar-Kashmere Gate, Safdarjung's Tomb-Qutub Minar, Humayun's Tomb-Safdarjung's Tomb and Shahjahanabad will be developed as heritage circuits.

According to officials, MPD41 will now be sent to the Union housing and urban affairs ministry for gazette notification.

"The master plan emphasises regeneration of brown fields, planned and unplanned areas covering old and dilapidated godowns clusters and industries operational in 26 non-confirming areas. Though these points were mentioned in the first draft, we have fixed timelines for them," said a senior DDA official. "MPD41 gives people the opportunity to demolish and reconstruct their old and dilapida-ted properties." Old godown clusters in non-conforming are as can also be regularised now

WHAT'S IN STORE

DRAFT MASTER PLAN 2041 APPROVED BY LG

- > Decision taken to relax guidelines pertaining to female beneficiaries of in situ rehabilitation under ahan Jhuggi Wahan Makan' programme
- Focus on inclusive development environmental sustainability, green economy, infrastructure development, sufficient housing for all sections, innovative interventions like transit-oriented development hubs, landpooling, development of green area, and rejuvenation and regeneration of the city
- > Development-control norms related to use of premises, parking requirements. mixing of uses
- GIS-based landuse plan developed to enable stakeholders to understand applicability of policies/provisions under draft Master Plan

Other highlights

- > Development of nonownership/ rental housing and affordable rental housing complexes
- Draft plan permits flexible loading of floorarea ratio (FAR)
- Provisions made for regeneration of existing/ brown-field areas through retrofitting, reconstruction or area-level redevelopment
- It will cover planned, unplanned, non-conforming godowns and industrial clusters
- Regeneration in old and dilapidated areas while fulfilling demands for social infrastructure in dense areas: foster walkable mixed-use neighbourhoods
- Compact and sustainable development through TOD-based projects to bring jobs and homes closer to

mass transit

Green steps

> Plan prioritises protection and improvement of 'green-blue' assets. This includes biodiversity parks, integrated floodplain planning and revival of baolis/waterbodies

- Buildings will also be required to meet green-blue factor conditions to ensure sustainable development
- Proposes rejuvenation of the Yamuna and its floodplain through a comprehensive plan

Promoting clean economies

- Such as IT/ cyber hubs, knowledge-based industries, R&D facilities and night-time economy
- Providing development strategies for hubs and centres, and modernisation of existing district centers

City hubs



- Promote development of cultural and entertainment hubs
- Emphasises on the development of city hubs, circuits. plazas and night-time circuits

Transport infra

- A comprehensive mobility plan to achieve systemic integration across all levels and modes of urban transport
- Parking management and green mobility, such as the use of e-vehicles and e-charging infrastructure

after rebuilding them as per the master plan norms.

Explaining the concept of regeneration of an area, an official said, "Facilities and open spaces in the city have become inadequate with steady growth in population. The existing built stock in many areas is old and derelict. There is a requirement of regeneration as well as strategic interventions to unlock the latent potential of certain areas in the city'

PD41 also proposes to boost housing supply by private participation through land pooling and regeneration of planned and unplanned areas with incentive FAR. It encourages development of non-ownership/rental housing, particularly in places close to mass transit, with new formats like serviced apartments, condominiums, hostels. student housing, etc.

The plan also prioritises protection and improvement of good quality green-blue assets for active/passive recreation and leisure. A press statement later identified these as "biodiversity parks, integrated floodplain planning, revival of baolis and water bodies, development of walking and cycling trails and rejuvenation of drain buffers'

There are now guidelines for the conservation of over 1,700 heritage sites. The official said, "There are structures belonging to ASI, MCD, Delhi government, DDA and individuals, many of whom own havelis. MPD41 promotes the protection and conservation of such havelis through transferable conservation rights to allow purchase of development rights to these places and conservation under the guidelines while the original rights

vest with the owner." The guidelines will likely motivate people to conserve heritage buildings notified by local bodies. These are mostly privately-owned and in active use by the occupants. Many of these are under severe threat due to disrepair, incompatible use and insensitive reconstruction of full or part.

The master plan also stresses a comprehensive mobility plan (CMP) for Delhi to achieve systemic integration across all levels and modes of urban transport. Said an official: "Given that the efficiency of urban transport depends \on seamless integration among road-based, rail-based, intermediate public transport and walking/cycling systems, Delhi needs a CMP involving all agencies.

MPD41, which was supposed to have been implemented earlier this year, got delayed for various reasons, including pending finalisation of the green development area policy, amendments in DDA Act and delay in incorporation of suggestions made by the public. Last September after the Supreme Court observed that the master plan couldn't remain in limbo, DDA assured it would be placed before the authorities in December, sent to the housing ministry in January and the final document published by April 30.

AAP MLA and DDA ment ber Somnath Bharti felt MPD41 shouldn't be passed in a hurry. In a letter to the LG, he said two days were given to read through the 300 pages. "The inadequate time given to read through the document is an injustice to me and Delhi's people. The master plan shouldn't be passed without giving proper consideration," he wrote

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

अमरउजाला

नई दिल्ली बुधवार, 1 मार्च 2023

--DATED-

20 साल के विकास का खाका तैयार, तीन करोड़ आबादी को घर मुहैया कराने पर जोर

मास्टर प्लान 2041 के मसौदे को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी, पर्यावरण संरक्षण पर फोकस

अमर उजाला ब्युरो

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अगले बीस सालों के लिए राजधानी के विकास का खाका तैयार किया है। मास्टर प्लान-2041 के मसौदे में तीन करोड़ आबादी के लिए घर और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। सभी बुनियादी सुविधाओं के विकास में पर्यावरण संरक्षण पर फोकस रहेगा। मास्टर प्लान में नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार को डीडीए बोर्ड की बैठक में मास्टर प्लान-2041 के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसे अब केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। मसौदे के अनुसार दिल्ली की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए



पार्किंग भी कराएंगे मुहैया

डीडीए अपनी सभी आवासीय योजनाओं के साथ पार्किंग भी मुंहैया कराएगा। यही नहीं, मास्टर प्लान में अपार्टमेंट, हॉस्टल, पीज़ी, श्रमिक आवास, किराए के आवास परिसर के विकास का भी प्रस्ताव है। इसके साथ, पुराने मकानों को मौजूदा जरूरतों के हिसाब से दुरुस्त भी किया जा सकेगा।

लैंड पुलिंग पॉलिसी, आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत सार्वजनिक स्थान, पुरानी सोसायटी में अतिरिक्त फ्लोर एरिया

घर में सुनिश्चित होगा महिलाओं का स्वामित्व : मसौदे के अनुसार आवासीय इकाइयों के आवंटन में पति व पत्नी का नाम साथ-साथ होगा। इससे महिलाओं का स्वामित्व सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रदूषण में लाई जाएगी कमी

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मास्टर प्लान में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत ज्यादा जोर हरित क्षेत्र के विकास पर रहेगा। हर प्रोजेक्ट के साथ पर्यावरणीय मानकों का ध्यान रखना होगा।

- वाहन प्रदूषण में कमी के लिए सार्वजनिक परिवहन के सभी माध्यमों में तालमेल की कोशिश होगी। अंतिम ग्राहक तक कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया है।
- मसौदे में ई-वाहन चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के विकास का भी प्रावधान है। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। इससे प्रदूषण स्तर में कमी आएगी।

रेश्यो देने के साथ हरसंभव विकल्पों का इस्तेमाल कर अतिरिक्त मकानों का निर्माण होगा। >> जीवंत दिल्ली को निर्माण का लक्ष्य: पेज उ

यमुना के विकास पर भी खास ध्यान

यमुना के पानी को साफ करने के साथ ही मास्टर प्लान में यमुना के बाढ़ क्षेत्र का भी कायाकल्प करने का प्रावधान है। मास्टर प्लान में व्यापक नदी विकास योजना की बात है। इसमें यमुना के इको सिस्टम को ध्यान में रखकर नम भूमि, बावली व नालों के बफर क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा।

नालों व नदी किनारे बफर जोन बनेगा। इसमें पैदल व साइकिल पथ के साथ बैठने को भी इंतजाम होगा। वहीं, नाले की सफाई पर भी जोर दिया गया है। इससे नाले के किनारे चलते-चलते प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा लिया जा सकेगा।

मास्टर प्लान 2021 की समय सीमा करीब दो साल पहले पूरी हो गई थी। इसकी जगह मास्टर प्लान 2041 को लेना था, पर अभी तक

यह तैयार नहीं हो सका था। अब अधिसूचित होने का इंतजार है। दरअसल, मास्टर प्लान सांविधिक दस्तावेज है। यह मौजूदा स्थिति का आकलन करने के साथ आने वाले बीस सालों की जरूरतों को ध्यान में रखता है।

रेस्तरां, आवास के लिए 49 दिनों में जारी होगा लाइसेंस

एकीकृत पोर्टल शुरू, देरी हुई तो स्वतः जारी होगा

नई दिस्सी। आतिथ्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेस्तरां, आवास और बोर्डिंग प्रतिष्ठानों



के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया आसान करने के लिए मंगलवार को संशोधित एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया। उद्यमियों, व्यवसायियों और स्टार्टअप के लिए लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया फेसलेस (ऑनलाइन) कर दी गई है। इसके माध्यम

से आवेदन करने पर 49 दिनों में लाइसेंस जारी करना होगा। देरी होने पर लाइसेंस स्वतः जारी किया जाएगा। >> पेज 3

वीके सक्सेना

amarujala.com

नई दिल्ली | बुधवार, 1 मार्च 2023

डीडीए के नये मास्टर प्लान में जीवंत दिल्ली के निर्माण का लक्ष्य

अमर उजाला ब्युरो

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2041 को दो खंडों व 10 अध्यायों में विभाजित किया गया

है। इसका विजन सतत रहने योग्य और जीवंत दिल्ली को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दिल्ली के निवासियों के सुख और भलाई के लिए तीन लक्ष्यों को पूरा किया

जाएगा। यह मसीदा नागरिक और स्टेकहोल्डरों की व्यापक भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, आरडब्ल्यूए, टेडर्स और मार्केट एसोसिएशन, एनजीओ, संगठन,

प्रोफेशनल्स, विशेषज्ञ आदि शामिल हैं।

मुख्य बिंदू।

 पहले खंड में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था (व्यापार और वाणिज्य, थोक व्यापार, उद्योग और सरकारी कार्यालयों सहित), विरासत, संस्कृति और सार्वजनिक स्थान, आश्रय और सामाजिक अवसंरचना, परिवहन और गतिशीलता, और भौतिक अवसंरचना के छह अध्याय बनाए गए है।

 दूसरे खंड में स्थानीय विकास, योजना निगरानी, विकास संहिता और विकास नियंत्रण मानदंड के लिए रूपरेखा, जिसमें दिल्ली के भावी विकास के मार्गदर्शन देने के लिए स्थानिक रणनीति, योजना और विकास नियंत्रण मानदंड शामिल है।

मास्टर प्लान

 इस अध्यार्य में मास्टर प्लान के लिए योजना निगरानी और मुल्यांकन ढांचे को भी शामिल किया गया है जिसमें प्रगति की निगरानी के लिए प्रमख कार्य-निष्पादन संकेतक और आवधिक समीक्षा की सुविधा के लिए एक कार्यान्वयन ढांचा शामिल है।



मास्टर प्लान में नाइट लाइफ संस्कृति को बढ़ावा देने का भी इंतजाम है। खाने-पीने और घूमने-फिरने के शौकीन व युवाओं के

नाइट लाइफ को मिलेगा बढावा

लिए वाइब्रेंट नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट समेत दूसरे कई प्रावधान किया गया है। इससे खान मार्केट, हीज ख़ास सरीखे बाजार देर रात तक गुलजार रहेंगे।

मास्टर प्लान में खुली छत पर भी रेस्टोरेंट पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत दायरे में लगाया जा सकेगा। रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष कॉरिडोर की पहचान की जाएगी। इन पर लाइटिंग के साथ सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम रहेगा।

2041 तक तीन करोड की होगी आबादी

मास्टर प्लान में डीडीए का अनुमान है कि दिल्ली की 2041 तक की आबादी करीब तीन करोड़ की होगी। 2021 के आधार वर्ष पर अभी यह दो करोड़ से ज्यादा है। 2031 तक यह आंकड़ों 2.48 करोड़ हो जाएगा,जबिक 2036 तक इसके 2.69 करोड़ होने का अनुमान है। मास्टर प्लान में इस आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनियादी सुविधाओं के विकास का प्रावधान है।

 1962 में लागू हुआ था पहला मास्टर प्लान दिल्ली के लिए पहला मास्टर प्लान 1962 में डीडीए एक्ट 1957 के तहत लागू किया गया था। इन योजनाओं को 20 साल की परिप्रेक्ष्य अवधि के लिए तैयार किया गया है और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करते हैं। मास्टर प्लान-2041 दिल्ली के भावी विकास को

दिशा प्रदान करने के लिए एक 'कार्यनीतिक' और 'सश्रम' ढांचा तैयार किया गया है।

अब रेस्तरां, बोर्डिंग प्रतिष्ठानों और आवास का लाइसेंस लेना आसान

एलजी ने संशोधित एकीकृत पोर्टल का किया शुभारंभ, आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

अमर उजाला ब्यूरो.

नर्ड दिल्ली। आतिथ्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेस्तरां, आवास और बोर्डिंग प्रतिष्ठानों के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने संशोधित एकीकृत पोर्टल का शभारंभ किया। एकल खिडकी की शुरुआत से आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों. व्यवसायियों और स्टार्टअप के लिए लाइसेंस हासिल फेसलेस (ऑनलाइन) कर दी गई है।

पुलिस. एमसीडी. प्रनडीएमसी, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से अब लाइसेंस लेने या इसका नवीनीकरण भी इस पोर्टल से कर सकेंगे। सभी एजेंसियों से 49 दिनों से लाइसेंस जारी करना होगा। इसमें देरी होने पर आवेदक के नाम लाइसेंसे स्वतः जारी किया जाएगा। इस पहल से रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को भी बढावा मिलेगा। इससे दिल्ली में भी देश विदेश की तर्ज पर अग्रणी सेवाएं मिल सकेंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि इस कदम से एक विनियमन में सुधार, सरलीकरण देर रात तक छतों पर बने रेस्तरां में भी परोसा जाएगा खाना



दिल्ली के भोजनालयों और रेस्तरां, डीडीए की ओर से संचालित क्लबों द्वारा संचालन के समय को बढ़ाने जैसे उत्साहजनक प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह अल्फ्रेह्सको और छतों पर खुले में खाने की अनुमति मिलने से अब एनसीआर के शहरों में जाने वाले भी देर रात तक दिल्ली में इन प्रतिष्ठानों में सेवाएं मुहैया की जाएंगी। संशोधित पोर्टल में लाइसँस देने और नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और फेसलेस कर बनाया गया है। अब पोर्टल पर बहुत छोटा, सरल और सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) जमा करके अपने लाइसेंस या इसका नवीनीकरण करने में सक्षम होंगे। यह सीएएफ सभी 05 लाइसेंसिंग निकायों के लिए लागू होगा। इसमें दिल्ली पुलिस, एमसीडी, एनडीएमसी, डीपीसीसी और दिल्ली फायर सर्विस शामिल हैं।

फॉर्म के लिए कम दस्तावेज की होगी जरूरत

नए सीएएफ के लिए 24 दस्तावेज को ही अपलोड करना होगा। पहले 52 दस्तावेज को फॉर्म के साथ अपलोड करना होता था, जिसे अब सरल बना दिया गया है। अब पांच निकायों के लिए एक ही अंडरटेकिंग जमा करने की जरूरत होगी। लाइसँस के नवीनीकरण के लिए दस्तावेज की संख्या कम करने से भी लाइसेंस हासिल करना और आसान हो जाएगा। सभी एजेंसियों के लिए लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)की वैधता बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। पहले विभिन्न एजीसवों के लिए वैधता एक से पांच वर्ष थी। इसके लिए एक आवेदक को नवीनीकरण के लिए इधर-उधर भागना पड़ता था।

होगा। आतिथ्य क्षेत्र के लिए नियम और शतें कठिन होने की वजह से उद्यमियों को मुश्किलें पेश आ रही थीं। प्रधानमंत्री के ईज ऑफ ड्रइंग बिजनेस के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए इस दिशा में पहल की गई है। सरल लाइसेंसिंग

दिन के भीतर

मिलेगा लाइसेंस

प्रक्रिया

फेसलेस, कम

दस्तावेज की

होगी जरुरत

मानदडों से आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा (गृह) के अधीन एक उच्च स्तरीय मिलने के साथ ही रात्रिकालीन समिति गठित की गई थी। एलजी ने अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी।

मौजुदा लाइसेंस व्यवस्था की कमियों और उद्यमियों व नागरिकों की , इसके परिणाम के तौर पर एकीकृत

कहा कि समिति रिकॉर्ड समय में अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम स्ही है। सहलियत को देखते हुए प्रधान सचिव पोर्टल की शुरुआत की गई है।



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भारकर नई दिल्ली, बुधवार, 01 मार्च, 2023

अमरउजाला

गोसिया कॉलोनी के 467 लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेज की सूची तलब

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महरौली में विध्वंस मामले-में गोसिया कॉलोनी झुग्गी के 467 लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेजों की एक सूची मुहैया करने को कहा है। इस मामले को 14 मार्च के लिए अगली सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने वकील अनुप्रधा सिंह से बधेवार तक डीडीए और इसिब के वकील को प्रभावित लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेज की सूची मुहैया करने को कहा है। पीठ ने डीडीए और दूसिब की ओर से दायर हर्सफनामे का जवाब दाखिल करने को भी कहा है।अधिवक्ता अनुप्रधा को अदालत ने इसके लिए एक महरौली मामले को हाईकोर्ट में चुनौती, अब 14 मार्च को होगी अगली सुनवाई

सप्ताह का समय दिया है। डीडीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि जिस जमीन की बात की जा रही है वह दक्षिण मध्य दिल्ली का हिस्सा है और महरौली पुरातत्व पार्क के तहत है। रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में विश्व प्रसिद्ध एतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। इनकी देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि डीडीए के भीम रिकॉर्ड के मताबिक खसरा नंबर 216 वे 217 लाडोसराय में है और इसे हरित क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। शुरू से ही इसे दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाना है और महरौली विरासत क्षेत्र में होने की वजह से इसे हरित क्षेत्र के तौर पर बनाया और संरक्षित करना है।

मास्टर प्लान 2041 को उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दी मंजरी

नई दिल्ली दिल्ली के लिए शुक्रवार महत्वपूर्ण रहा। तीन घंटे के मैराथन बैठक में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष ने मास्टर प्लान 2041 की मंजरी दे दी। उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि इससे विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी और राष्ट्रीय राजधानी के भावी विकास को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस बैठक में डीडीए ने 'जहां झग्गी वहां मकान' कार्यक्रम के तहत पुनर्वास के लिए महिला लाभार्थियों से संबंधित दिशा-निर्देशों में ढील देने का भी निर्णय लिया। बैठक की शुरुआत करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली मख्य योजना-2041 में समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रीन इकॉनामी, आधारिक संरचना के विकास पर जोर दिया गया है।

महरौली ध्वस्तीकरण मामलाः हाई कोर्ट ने निवासियों से मांगे पहचान दस्तावेज

महरौली में डीडीए की ओर से की जा रही तोडफोड की कार्रवाई

भास्कर न्युज नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को महरौली ध्वस्तीकरण मामले में एक बडा आदेश जारी किया। अदालत ने महरौली इलाके में गोशिया कॉलोनी झग्गी के निवासियों के वकील से कहा कि वे 467 निवासियों के पहचान संबंधी दस्तावेजों की सूची



अदालत के समक्ष प्रस्तृत करें। इसके साथ ही अदालत ने सनवाई के लिए 14 मार्च तारीख तय की।

बता दें कि निवासियों ने डीडीए की ओर से कॉलोनी में की जा रही तोडफोड़ की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। न्यायमुर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अधिवक्ता अनप्रधा सिंह से बधवार तक डीडीए और डीयएसआईबी के वकील को पहचान दस्तावेजों की सूची सौंपने के निर्देश दिए। यही नहीं अदालत ने उन्हें डीडीए और डीयूएसआईबी की ओर से दाखिल हलफनामों पर भी जवाब देने को कहा गया है। इस पर अधिवक्ता अनुप्रधा ने हलफनामों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते की मोहलत दी है।

1 मार्च ● 2023

सहारा

पंजाब केसरी

दिल्ली की सूरत बदल देगा नया मास्टर प्लान 2041



■ राजनिवास में आयोजित बैठक में उप-राज्यपाल ने लगाई मुहर ■ लोगों को देगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली

■ जहां झुग्गी-वहीं मकान योजना, के तहत महिलाओं के नाम होगा फ्लैटों का आवंटन नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को नए मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी। प्राधिकरण अध्यक्ष एवं उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का मानना है कि नया मास्टर प्लान देश की राजधानी दिल्ली की सूरत को बेहतर बनाने बाला साबित होगा और इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राजनिवास में संपन्न हुई डीडीए की इस बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों समेत सभी आला अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि नए मास्टर प्लान में जहां झुगी-वहीं मकान योजना के तहत महिलाओं के नाम पर आवंटन पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरण का कहना है कि बैठक में जहां झुगी-वहीं मकान जैसी योजनाओं में महिलाओं को प्रमुख रूप से छुट देने का निर्णय िलया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि मास्टर प्लान में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की पहल की गई है। इसमें प्रमुख रूप से सभी बेघरों को आवास मुहैया कराना, लैंड पूलिंग, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट और शहर का कायांकल्प कर उसे पुनर्जन्म देना शामिल है। नया मास्टर प्लान दिल्ली के विकास को और सुगम बनाकर गति देगा। लोगों को बेहतर पर्यावरण के साथ अच्छा माहौल मिलेगा। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार कर लोगों को गुणवत्ता युक्त, किफायती और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।

मास्टर प्लान में जहां लोंगों के बेहतर जीवन शैली देने की कोशिश की गई है, वहीं बुनियादी सुविधाओं में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने विरासत, संस्कृति और सार्वजनिक स्थान, परिवहन को मजबूत बनाने पर फोकस किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मास्टर प्लान में यमुना नदी के कायाकल्प का भी प्रस्ताव है। प्राधिकरण के अधिकारी ने नए मास्टर प्लान के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मास्टर प्लान का यह मसौदा लोगों को केंद्र बिंदु में रखकर तैयार किया गया है। सभी हितधारकों, विभाग, स्थानीय निकाय, आरडब्ल्यूए, व्यापारी, बाजार संघ, गैर सरकारी संगठन, संगठन, पेशेवर, विशेषज्ञ एवं अन्य लोगों के भविष्य का ध्यान रखा गया है।

महरौली तोड़फोड़ मामला 14 मार्च को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने निवासियों के पहचान दस्तावेजों की मांगी सूची

नर्ड दिल्ली. (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महरौली में घोसिया स्लम कॉलोनी के निवासियों के वकील से 467 निवासियों के पहचान दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करने के लिए कहा। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 14 मार्च को सूचीबद्ध किया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने वकील अनुप्रधा सिंह से बुधवार तक डीडीए और डीयूएसआईबी के वकील को पहचान दस्तावेजों की एक सूची देने को कहा। बेंच ने उन्हें डीडीए और डीयूएसआईबी द्वारा दायर हलफनामों पर एक प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी कहा है। वकील अनुप्रधा ने हलफनामों पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा। बेंच ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है।

डीडीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि विचाराधीन भूमि महरौली पुरातत्व पार्क में आती है जो दक्षिणी मध्य रिज का हिस्सा है जहां बडी संख्या में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध स्मारक मौजूद हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित/असंरक्षित और अनुरक्षित हैं (एएसआई)। हलफनामे में कहा गया है कि डीडीए द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड के अनुसार यह पेश किया गया है कि खसरा संख्या 216 और 217 गांवों के खसरा सराय महरौली नई दिल्ली में वर्तमान याचिका की भूमि विषय वस्त् झुठी है, यह भी पेश किया गया कि खसरा संख्या 217 एक अधिग्रहीत भूमि है। बेंच को बताया गया कि इस



भूमि को शुरू से ही दिल्ली के मास्टर प्लान में हरे रंग के रूप में चिह्नित किया गया है और इसे हरित के रूप में विकसित और बनाए रखा जाना है और महरौली विरासत क्षेत्र के तहत संरक्षित किया जाना है। कहा गया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस क्षेत्र को आराम के लिए आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कुतुब से अधिक अंधेरिया जाने वाली सडक के पश्चिमी भाग में स्थित है। 17 फरवरी को अदालत ने डीडीए और डीयूएसआईबी को महरौली में घोसिया स्लम कॉलोनी के निवासियों की याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। बेंच ने डीडीए के स्थायी वकील से दस्तावेजों और गूगल छवियों के साथ एक हलफनामा दायर करने को कहा था। हाईकोर्ट ने डीयूएसआईबी के वकील से याचिकाकर्ता कॉलोनी को अधिसूचित जेजे क्लस्टर की सूची में जोड़ने और बाद में इसे हटाने के लिए आधार का उल्लेख करने के लिए भी कहा था। याचिका घोसिया कॉलोनी सेवा समिति और अन्य ने बकील अनुप्रधा सिंह के माध्यम से दायर की है।



Wednesday, March 1, 2023

DATEL

The high-decibel defenders of Delhi

Mehul Malpani

NEW DELHI

"Forget about sleeping, you can't even lie down in peace with the loud music and noise when there is a function in your lane or neighbourhood," said Gagan Maheshwari, 46, a resident of Rohini's Prashant Vihar. "But that's the kind of adjustment you have to make as a neighbour," he added.

In 2022, Delhi Police received 46,815 noise pollution-related complaints out of which 40,091 were against DJ music at weddings and other events, as per the official data shared by a senior officer.

While most complaints were received on the police's 100 and 112 emergency helplines, 2,286 calls were also received on the 24x7 dedicated helpline for noise pollution grievances 155271.

Another senior officer said that the maximum calls were received during Legal action can be taken against offenders under provisions of the Delhi Police Act

the festival and the wedding season. "The number of calls increases in the evening and night," he added. Many people living in Delhi have informal outdoor arrangements for gatherings. They erect tents down their lanes and may flout the no-loud-speakers-after-10 p.m. rule instituted in 2005.

Rashmi Mehta, 48, a resident of Green Park, said that there is a temple next to her house with frequent post-10 p.m. activity.

"People organise Devi jagrans or keertans with loud music," she says, adding that when it's a religious function, it's difficult to say anything. "Last year, both my son and daughter had their Board exams so during one such event, I had to go the temple and request them to reduce the volume." They reduced the volume only a little.

Legal provisions

Deputy Commissioner of Police (PRO) Suman Nalwa said, "Local police can take legal action under the provisions of the Delhi Police Act Sections 29, 32, and 113, and the Environment (Protection) Act Sections 5 and 15." Ms. Nalwa also said that the organiser must seek permission from the district deputy commissioner of police (DCP) before getting the no-objection certificate from the traffic unit and Municipal Corporation of Delhi (MCD) or Delhi Development Authority (DDA) to organise a public function.

However, a Residents'
Welfare Association (RWA)
president from Malviya Nagar said that in most cases
people don't take the necessary permissions.
"They just inform the local
RWA so that we can make

arrangements, such as opening alternate society gates or shifting cars parked in the lane to somewhere else," she said.

Ravinder Singh, 47, who used to run a DJ company in Kalkaji, said that it was difficult to turn down the music because it would mean refusing drunk clients. "Drunk people force the DJ staff to keep playing even after the permitted time. They also get aggressive if we refuse to play or lower the volume."

A tent house owner, Mohammad Suhail, 32, also said that at many functions, people tend to play music till 2-3 a.m. "What can we or the DJ do?" he added.

Another police officer, however, said that it is the DJ's responsibility to stop the music in time. Violations – the use of loud speakers or public address systems after 10 p.m. – are punishable with a fine of ₹10,000 and seizure of equipment.

millenniumpost
NEW DELHI | WEDNESDAY, 1 MARCH, 2023

DATED

DDA approves Master Plan 2041

SATVIKA MAHAJAN

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has approved the draft Master Plan 2041 for the Capital.

The decision was taken during a marathon meeting that went on for more than three and a half hours at the Raj Niwas here. It was chaired by the Lt Governor (L-G), who is also the chairman of the DDA, officials said.

The Authority in its meeting, also took a decision for relaxation in guidelines pertaining to female beneficiaries for in situ rehabilitation under Jahan Jhuggi Wahan Makan programme.

The Draft MPD-2041 is a 'strategic' and 'enabling' framework to guide future growth of the city, built upon the lessons learnt from the implementation of the previous plans and based on learning's from across the country with respect to implementation of various projects and schemes, as per DDA officials.

Saxena said that, the thrust of MPD-2041, was inclusive development, environmental sustainability, green economy, infrastructure development that included sufficient housing for all sections of the society, innovative interventions like TOD Hubs, Land Pooling, Green Area Development and Rejuvenation and Regeneration of the city. MPD-2041 has been divided into 2 Volumes, 10 Chapters with a vision to "Foster a Sustainable, Liveable and Vibrant Delhi".

The three major goals in this plan includes, movement to make Delhi an environmentally sustainable city that provides a healthy environment for its citizens that is resilient to impacts of climate change and disasters. Develop as a future-ready city that offers good quality, affordable and safe living environments with efficient services and green mobility systems.

Emerge as a dynamic place for economic, creative and cultural development.

As per DDA officials, MPD-2041 is prepared based on extensive citizen and stake-holder engagement which includes Govt. Departments, Local Bodies, RWAs, Traders and Market Associations, NGOs, Organisations, Professionals, experts and Individuals etc. which form the basis of the exercise for vision of future for Delhi.

The Draft Plan prioritises protection and improvement of good quality green-blue assets for active/passive recreation and leisure. This includes biodiversity parks, integrated floodplain planning, revival of baolis/ water bodies, development of walking and cycling trails along with the rejuvenation of drain buffers. Buildings will also be required to meet Green-Blue Factor (GBF) conditions to ensure sustainable development practices. Addi-

tionally, the plan also proposes the rejuvenation of the Yamuna River and its floodplain through preparation of the Comprehensive River Development Plan for river Yamuna.

Plan proposes to encourage the development of a night time economy for safe and a vibrant city, it also includes norms for heritage zones, archaeological parks, and cultural precincts, as well as instruments for improving conservation of heritage building to promote Delhi's rich history and culture. MPD-2041 will be forwarded to the Ministry of Housing and Urban Affairs for final approval and notification.

Earlier in the day, AAP MLA and DDA Member Somnath Bharti wrote to DDA Chairman, Delhi L-G seeking postponement of meeting on Master Plan 2041. The MLA cited in his letter that DDA has not given sufficient time to residents to review and suggest changes to the MPD-2041.

No role of DUSIB in DDA's demolition drive in Mehrauli, HC told

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) on Tuesday told the Delhi High Court that it has no role in the demolition drive proposed by the DDA in Mehrauli or rehabilitation of displaced residents. DUSIB said the land-owning agency is the Delhi Development Authority and the board has no role to play in the petition filed by Ghosiya Slum Colony in Mehrauli, which was to be demol-

ished by the authorities.

"Evidently, in the instant case, the alleged demolition drive is proposed by the respondent no. 1 (DDA). It is further submitted that the land-owning agency, as per the petitioner (slum colony) in the present case, is DDA.

"Therefore, in view of this, in so far as the answering respondent (DUSIB) is concerned, it has no role in demolition or rehabilitation of the petitioner," DUSIB said in an affidavit filed in response to the petition.

The matter came up before



Justice Manmeet Pritam Singh Arora who listed it for further hearing on March 14. DUSIB said DDA is the state level nodal agency for in-situ rehabilitation of slum dwellers (in respect of lands belonging to the Central government and its agencies) under the Pradhan Mantri Awaz Yojna-Housing For All (Urban) in Delhi. It said no joint survey of the colony has been carried out with the representatives of DDA as per the Delhi Slum Rehabilitation Policy of 2015 and "since the land owning agency in this case is DDA, therefore, any steps as for the rehabilitation, relocation or under in-situ up-gradation, if at all to be done, needs to be done by the DDA."

DDA, which also filed an affidavit in response to the petition, said factually the colony is not a slum cluster and it is evident from the image taken from Google Earth of Ghosiya Colony of 2006, 2008 and 2010

that the "entire area was green".

Subsequently around 2012, erection of jhuggies commenced and at the end of that year, the DDA sought police assistance for demolition of juggis from the colony and removed all of them, it said.

"Image taken from Google Earth in March 2022 shows encroachment in the same area," DDA said. The court has passed an interim order directing the authorities to maintain the status quo on 400 jhuggis of the slum colony.

NAME O Wednesday, March 1, 2023



L-G approves draft MPD-2041

NEW DELHI

Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Tuesday approved the draft Master Plan for Delhi-2041 at a meeting of the Delhi Development Authority. He said the plan's thrust is on inclusive development, sustainability and innovative interventions. » Page 3

Draft MPD-2041 approved by L-G, focus on housing for all

Draft Master Plan also aims to promote city's night-time economy, rejuvenate the Yamuna; sufficient time not given to residents to review changes, AAP MLA Somnath Bharti tells Saxena

The Hindu Bureau NEW DELHI

ieutenant-Governor V.K. Saxena on Tuesday approved the draft Master Plan for Delhi-2041 (MPD). Mr. Saxena, who is also the chairperson of the DDA, said the thrust of the plan is on inclusive development, environmental sustainability, green economy, transitdevelopment oriented hubs, land pooling and housing for all.

The draft MPD-2041 also proposes to promote the city's night-time economy, heritage, industrial activity and rejuvenate the Yamuna river through a Comprehensive River Development Plan. The draft Master Plan will now be forwarded to the Ministry of Housing and Urban Affairs for final approval and notification.

The Master Plan, pre-

pared by the DDA, is a statutory document that facili-Capital's tates the development by assessing the present condition and guiding how to achieve the desired development. "The draft MPD-2041 is a strategic and enabling framework to guide future growth of the city, built upon the lessons learnt from the implementation of the previous plans," the DDA said in a statement.

DDA's three goals

The DDA said it would pursue three goals stated in the Master Plan over the next 18 years. The first goal is to become an environmentally sustainable city that is resilient to the impact of climate change. The second is to become a future-ready city offering good quality, affordable and safe living environments to its citizens. The third goal is to emerge as



The thrust of the plan is on inclusive development, environmental sustainability, green economy and housing for all

V.K. SAXENA Delhi Lieutenant-Governor

"a dynamic place for economic, creative and cultural development".

The vision document also includes "the development of affordable rental housing complexes with service apartments, con-

dominiums, hostels etc." the agency said in its statement.

The Master Plan also proposes the preparation of a comprehensive mobility plan (CMP) to integrate land use and transportation, transit-oriented development, and strategic mobility corridors intra-city and inter-city movement while promoting the use of e-vehicles e-charging infrastructure.

Earlier in the day, AAP MLA and DDA member Somnath Bharti wrote to Mr. Saxena seeking the postponement of the meeting. The MLA said that the DDA had not given sufficient time to residents to review and suggest changes to the draft MPD-2041. Mr. Bharti accused the DDA of being solely responsible for unauthorised construction and giving builder mafia a free hand.

पंजाब केसरी ▶ १ मार्च, २०२३ ▶ बुधवार

DATED

ग्रप हाउसिंग सोसायटियों के लिए ४०% तक ग्राउंड कवरेज...

डीडीए के मास्टर प्लान 2041 को दी उपराज्यपाल ने मंजूरी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी के विकास और उसकी तरक्की के लिए डीडीए के अध्यक्ष व दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मास्टर प्लान 2041 को मंजरी दी है। एलजी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान "जहां झुग्गी वहां मकान" के तहत इन सीटू पुनर्वास के लिए महिला लाभार्थियों से संबंधित दिशा-निर्देशों में ढील देने का भी निर्णय लिया गया। साढे तीन घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में एलजी ने कहा कि मास्टर प्लान-2041 में समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रीन इकॉनामी, आधारिक संरचना के विकास पर जोर दिया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त आवास, टीओडी हब, लैंड पुलिंग, हरित क्षेत्र का विकास, शहर का कायाकल्प और पुर्नरुद्धार जैसी नई परिकल्पनाएं शामिल हैं। इसके अलावा मास्टर प्लान में आईटी/साइबर हब, ज्ञान आधारित उद्योगों और दिल्ली में अनुसंघान एवं विकास सुविधाओं जैसी स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के साथ नाइट इकोनॉमी के विकास के लिए भी प्रावधान है। डीडीए मास्टर प्लान में लैंड पूलिंग और रिजेनरेशन के माध्यम से निजी भागीदारी से आवास की आपूर्ति को बढ़ावा देना चाहता है। मास्टर प्लान

खास बातें...



- अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा
- औद्योगिक प्लॉट पर वर्कर हाउसिंग पर काफी जोर
- पार्किंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य
- मास्टर प्लान में ग्रीन व नाइट इकोनॉमी पर जोर

में कंप्रिहेंसिव रिवर डेवलपमेंट प्लान के तहत यमुना व उसके बाढ़ क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा हेरिटेज जोन व आर्किलॉजिकल पार्क सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमा तय की गई है। इसमें 25 से 60 वर्गमीटर के स्मॉल फार्मेट हाउंसिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी व निजी क्षेत्रों

की मदद से अफोंडेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बढावा देने का प्रावधान इस इस मास्टर प्लान का प्रमुख हिस्सा है। औद्योगिक प्लॉट पर वर्कर हाउसिंग पर भी काफी जोर दिया जाएगा। वहीं ग्रप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए 40 प्रतिशत तक का ग्राउंड कवरेज व वैक्लपिक साइटों पर ईडब्लयूएस हाउसिंग का प्रावधान इस मास्टर प्लान में किया गया है। इसके अलावा फॉरेन मिशन को बढ़ा हुआ ग्राउंड कवरेज व एफएआर दिये जाने की बात भी मास्टर प्लान में शामिल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए भी बढ़ा हुआ एफएआर दिया जाएगा। वहीं रेजीडेंशियल एरिया में हॉस्टल बनाए जाएंगे। अब पार्किंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना भी इस मास्टर प्लान में अनिवार्य किया गया है।

यहां बता दें कि एमपीडी -2041 का ड्राफ्ट नागरिक और स्टेकहोल्डरों की व्यापक भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, आरडब्ल्यूए, ट्रेडर्स और मार्केट एसोसिएशन, एनजीओ, संगठन, प्रोफेशनल, विशेषज्ञ और आम व्यक्तियों के विचार शामिल किये गये हैं। प्राधिकरण की बैठक में डीडीए वीसी सुभाषीश पंडा औरअन्य सदस्यों ने भाग लिया।

क्या है मास्टर प्लान

मास्टर प्लान 2041 डीडीए द्वारा तैयार एक सांविधिक दस्तावेज है, जो वर्तमान स्थिति का आंकलन करता है और वांछित विकास को प्राप्त करने हेत मार्गदर्शन करके दिल्ली के विकास को सगम बनाता है। डाफ्ट एमपीडी-2041 शहर के भावी विकास को दिशा प्रदान करने के लिए एक 'कार्यनीतिक' और 'सक्षम' ढांचा है, जो पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर बनाया गया है और विभिन्न परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में देश भर से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। दिल्ली के लिए पहला

है। दिल्ली के लिए पहेली मास्टर प्लान 1962 में दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत लागू किया गया था। इन योजनाओं को 20 साल की परिप्रेक्ष्य अविध के लिए तैयार किया गया है और ये दिल्ली के नियोजित विकास के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

he pioneer

NEW DELHI I WEDNESDAY I MARCH 1, 2023

Master Plan 2041: Boost to night economy, green growth

LG nod to draft MPD-2041

STAFF REPORTER IN NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Tuesday approved the Master Plan for Delhi (MPD) 2041 at the Delhi Development Authority (DDA) meeting which will usher a new era of development and will guide future growth of the national Capital.

The draft MPD 2041 will be forwarded to Ministry of Housing and Urban Affairs for final approval and notifi-cation. The Master Plan proposes to promote clean economies such as IT/cyber hubs, knowledge-based industries, and R&D facilities in

There is also provision for the development of night time economy. As part of the master plan, the authority wants to boost housing supply, by pri-vate participation through land pooling and regeneration of

At the meeting, the Authority also took a decision for relaxation in guidelines pertaining to female beneficiaries for in situ rehabilitation under Jahan Jhuggi Wahan Makan programme. The new MPD 2041 will be

a more people-friendly document easy-to-read and understand by general public apart from professionals

GIS-based land use plan is developed which will enable stakeholders in ease of understanding of applicability of policies/provisions of draft Master Plan on ground more



norms related to use premises and activities, flexibility in use. parking requirements, mixing of uses, etc have been simplified and enable flexibility to meet future developments and

The MPD also emphasis on development of city hubs, circuits, plazas, and night time circuits. Specific corridors and

trails will be identified for promoting the night time economy; boost housing supply, by private participation through land pooling & regeneration of planned and unplanned areas with incentive FAR; plan proposes development of nonownership/Rental Housing and Affordable Rental Housing Complexes (particularly close

mats like serviced apartments, condominiums, hostels, student housing, worker housing, etc. to meet housing supply demand in existing developed

The main features also include plan proposes parking management and promotes green mobility, such as the use of E-vehicles and e-charging infrastructure; physical infrastructure plays a crucial role in urban development, as it provides the basic framework for any urban area to function and grow sustainably.

Strategies are provided for reuse of treated waste water, dual-piping systems, green rating, promotion of renewable energy, optimising utilisation of resources, waste management including C&D waste; plan permits flexible loading of Floor Area Ratio (FAR), Transfer of Development Rights (TDR) receiving areas, and additional development controls to promote walkability, sustainable design, active frontage, and other sustainable urban planning principles in land pooling areas.
The MPD also include

provisions made for regeneration of existing/ brownfield areas through retrofitting, reconstruction or area-level

redevelopment which shall covers planned areas such as planned residential colonies, Commercial, Industrial, PSP & BPD, and unplanned areas such as inauthorised colonies, Il clusters, urban villages, Non-Conforming Godown Clusters & Non-Conforming Industrial Clusters; Regeneration in the old and dilapidated areas, redensification of areas by providing incentives for planned redevelopment and/or retrofitting of areas; improve arealevel safety and disaster resilience and increase availability of social infrastructure and Improving social infrastructure in existing areas

lages and unauthorized The DDA also decided that for successful implementation of in-situ rehabilitation

colonies

through regeneration, particu-

larly dense areas like urban vil-

projects and in order to provide relief to the beneficiaries of all such projects, it was decided that possession letter may be issued in the single name of women spouse occupying the jhuggi in such cases

The first Master Plan for Delhi was promulgated in 1962 under the Delhi Development Act 1957.

These plans are prepared for 20years' perspective peri-ods and provided a holistic framework for planned development of Delhi.

The Draft MPD-2041 is a 'strategic' and 'enabling' framework to guide future growth of the city, built upon the lessons learnt from the implementation of the previous plans and based on learning's from across the country with respect to implementation of various projects and schemes

Unified portal for licensing of eating, lodging sectors to help startups

In an enabling move that will go a long way in giving a boost to the hospitality sector. Delhi Lt Governor Vinai Kumar Saxena on Tuesday launched the modified unified portal for licensing of eating, lodging and boarding estab-

This single window portal will help entrepreneurs, businessmen and start-ups in the hospitality sector by way of ensuring that a single easy to fill form, enables them to get / renew licenses from Delhi Police, MCD, NDMC, Delhi Fire Service and DPCC, simultaneously within a fixed timeframe of 49 days.

Establishments will now be able to operate under a much simplified, minimal and enabling licensing regime, in the National Capital.

Speaking on the occasion, the LG said this major step has reformed, simplified and over-hauled a regulation that had been existing since 1980 and had become extremely obstructionist for the entrepreneurs in



the hospitality sector. Taking on from the Prime Minister's dictum of "Ease of Doing Business", Saxena said gover-nance should be about enabling, endeavour and enterprise and not obstructing and restricting them.

Addressing the gathering of restaurateurs, hoteliers and others, the LG said enabling the hospitality sector, with these simplified licensing norms, would prove to be the first step in the direction of a robust

Night Time Economy in Delhi Since the edsting increase regime in the city was found to be restrictive in terms of the requirements and demands of the entrepreneurs and people,

a High Level Committee under the Principal Secretary (Home), comprising top offi-cers from all stakeholder departments was constituted to ease the same, Saxena

The Committee was able to complete its task in record time and the result is there for all of us to see, in the shape of this "Modified Unified Portal for Licensing of Eating & Lodging / Boarding Establishments, launched

today, he further said.
It was informed that,
experiments like extending the
timings of operations by eateries and restaurants in the city and clubs run by the DDA, had

been encouraging. Similarly, alfresco and dinning on terraces were allowed. Residents of the city, who were going to establishments in the neighbouring hubs of NCR, got an option to patronise establishments in Delhi itself.

With the launch of modified portal, the entire process of granting and renewal of licenses has been made completely online and faceless Establishments in the hospitality sector will now be able to get their licenses or renew them by submitting a much shorter, simpler and userfriendly Common Application rhenay Common Application Form (CAF) on the portal. This CAF will be applicable for all 05 Licensing Bodies that include, Delhi Police, MCD, NDMC, DPCC and Delhi Fire Service. In the new CAF, 140 fields have been removed and uploading of 28 documents has been done away with Instead of 05 affidavits that was supposed to be subtritted ear-lier, the applicants will now have to submit a Single Common Undertaking for all 05 agencies.

